

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान वित्त वर्ष में तेजी से बढ़ने का अनुमान है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में 2004-05 के स्थिर मूल्यों (वास्तविक स.घ.उ.) पर उपादान लागत पर 8.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। यह 2009-10 में 8.0 प्रतिशत की संशोधित वृद्धि के बाद है जो संकट से तेजी से उबरने और समेकन का परिचायक है। 2010-11 में वास्तविक स.घ.उ. का वर्गवार विश्लेषण दर्शाता है कि वृद्धि के उच्चतर तथा प्रमुख सेक्टरों/उप-सेक्टरों, नामशः कृषि, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार और वित्तपोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबार सेवाओं; जिनका 2009-10 में स.घ.उ. का 82.6 प्रतिशत हिस्सा है, में सापेक्षिक रूप से व्यापक रहने का अनुमान है। वर्तमान राजकोषीय वर्ष के प्रथमार्थ में उद्योगों में राष्ट्रीय लेखा तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में तीव्र थी; परन्तु हाल के महीनों में कुछ गिरावट के संकेत हैं जो संरचनात्मक न होकर अस्थायी झटकों की तरह है; वर्तमान वित्त वर्ष में दूरसंचार सेवाओं, नागर विमानन और वित्तीय सेवाओं जैसे प्रमुख संकेतकों में सुदृढ़ निष्पादन के संदर्भ में 'सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं' के अपवाद को छोड़कर अधिकांश सेवाओं में सुधार हुआ है। इससे स.घ.उ. की वृद्धि के संकट पूर्व देखे गए मजबूत स्तरों के निकट पहुंचने में मदद मिली है। वर्तमान वित्त वर्ष (2010-11) में वैदेशिक क्षेत्र का घटनाक्रम समर्थनकारी रहा, वित्तीय बाजार सन्तुलित बने रहे और राजकोषीय समेकन ने पुनः गति पकड़ी। कृषि उत्पादन के आंकड़े लगभग सामान्य मानसून के चलते पैदावार में वृद्धि होने से इस क्षेत्र में पुनः वृद्धि का संकेत देते हैं। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापे गए मुद्रास्फीति के बढ़े हुए स्तर वर्तमान वित्त वर्ष के आरंभ में खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी के कारण थे, जो मांग-आपूर्ति में असंतुलन को दर्शाते हैं; परन्तु मुद्रास्फीति के सभी वस्तुओं में फैलकर एक आम घटना बनने का रूझान दिखाई दिया है। सकल मांग के उच्च स्तरों के मुद्रास्फीति के बढ़े हुए स्तरों (न केवल थोक मूल्य सूचकांक की दृष्टि से अपितु अन्तर्निहित स.घ.उ. अपस्फीतिकारी होने की दृष्टि से भी) के साथ जुड़ जाने से एक जटिल आर्थिक चुनौती पैदा हो गई है, जिसके लिए सोची-समझी संतुलित नीतियां अपनाने की आवश्यकता है ताकि वृद्धि से मिले लाभों को संजोए रखा जा सके और साथ ही निकट भविष्य में जनता की क्रयशक्ति में और कमी आने से रोका जा सके। इस संबंध में अपनाई गई मौद्रिक नीतियों ने मुद्रास्फीति को काबू में रखने की आवश्यकता को परिलक्षित किया और इनके साथ-साथ किए गए प्रशासनिक और राजकोषीय उपायों से मुद्रास्फीति को काबू में रखने में मदद मिली। मुद्रास्फीति में दिसम्बर 2010 में कुछ

मौसमी वस्तुओं की कीमतों में आए उछाल को छोड़कर, आमतौर पर गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है। वैश्विक संकट के परिणामिक प्रभावों के मंद पड़ने के साथ ही, मध्यावधि परिदृश्य उज्ज्वल बना हुआ है।

स.घ.उ. वृद्धि

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की प्रथम दो तिमाहियों के तिमाही वास्तविक स.घ.उ. अनुमान वर्तमान राजकोषीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 8.9 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दर्शाते हैं। तथापि, 31 जनवरी, 2011 को जारी त्वरित अनुमानों द्वारा 2009-10 के लिए वृद्धि के स्तरों में संशोधन के बाद, त्रैमासिक आधार पर 2010-11 में वृद्धि के भी संशोधित होने की संभावना है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2009-10 के अपने त्वरित अनुमानों में वास्तविक स.घ.उ. में वृद्धि को संशोधित कर 8.0 प्रतिशत किया (7.4 प्रतिशत के पहले अनुमानों की अपेक्षा)। यह 2008-09 में 6.8 प्रतिशत की संकट प्रभावित वृद्धि की अपेक्षा 2009-10 में तीव्रतर आर्थिक सुधार को दर्शाता है। 7 फरवरी, 2011 को जारी अपने अग्रिम अनुमानों में, सीएसओ ने वास्तविक सघउ में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि आंकी है जो समेकन का दौर दर्शाता है। वृद्धि के इस स्तर में कृषि में 5.4 प्रतिशत, उद्योग में 8.1 प्रतिशत और सेवाओं में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

वर्ष 2010-11 के वास्तविक स.घ.उ. में अनुमानित वृद्धि की संरचना दर्शाती है कि कुल में 82.6 प्रतिशत के हिस्से वाले प्रमुख सेक्टरों/उप सेक्टरों में वर्षानुवर्ष आधार पर उच्चतर स्तर पर वृद्धि हुई जो इसके व्यापक आधारयुक्त स्वरूप को दर्शाता है। 2008-09 और 2009-10 में ऋणात्मक और बहुत निम्न वृद्धि के बाद, कृषि और सम्बद्ध सेक्टर में वर्तमान वित्त वर्ष में आमूलचूल बदलाव आया और इसने समग्र स.घ.उ. वृद्धि में लगभग 9.2 प्रतिशत का योगदान किया। तथापि, कृषि में वृद्धि का स्तर समग्र स.घ.उ. वृद्धि से कम है, अतः वर्ष 2010-11 में स.घ.उ. में कृषि का हिस्सा घटकर 14.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्ष 2010-11 में 9.6 प्रतिशत की सेवाओं में वृद्धि संकट प्रभावित वर्षों सहित विगत 5 वर्ष में दर्ज 10.0 प्रतिशत से अधिक के स्तरों से गिरावट का संकेत देती है। तथापि, वर्ष 2010-11 के दौरान दो प्रमुख संघटकों, 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार' तथा वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यापार सेवाओं से निजी क्षेत्र की अगुवाई में सेवाओं की वास्तविक वापसी का और सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं में कमी का संकेत प्राप्त होता है, जो मुख्यरूप से आधार प्रभाव के कारण सरकारी कार्यकलापों के अनुरूप है। उद्योग क्षेत्र में लगभग समान स्तर पर वृद्धि होने का अनुमान जो भवन-निर्माण

क्षेत्र में तेजी (जिसे संकट-पूर्व स्तरों पर वापसी करना है) और विनिर्माण में उच्च और निम्न वृद्धि का वर्ष दर वर्ष में मिला-जुला रूप दर्शाता है। समग्र रूप से प्रमुख क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में उच्च स्तरों पर वृद्धि होने का अनुमान है जो वृद्धि का समेकन दर्शाता है और यह संकट-पूर्व मजबूत स्तर के नीचे है।

अनुमान की व्यय पद्धति की दृष्टि से स.घ.उ. में वर्ष 2009-10 (त्वरित अनुमान) की 9.1 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात 2010-11 में स्थिर बाजार मूल्यों पर 9.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। निजी अंतिम खपत व्यय, जिसमें विगत दो वर्षों में कमी आई थी, में चालू राजकोषीय वर्ष में वृद्धि होने का अनुमान है क्योंकि सरकारी अंतिम खपत व्यय में तीव्र कमी आई है और प्रोत्साहन राशि का आंशिक आहरण हुआ है। सकल पूंजी निर्माण में वर्षानुवर्ष कमी के कारण 'स्टॉक परिवर्तन' और 'बहुमूल्य वस्तुओं' में आधार प्रभाव पर तीव्र कमी आई है जिससे सकल पूंजी निर्माण में हुई पर्याप्त तेजी व्यर्थ साबित हुई है। जहां निर्यात में वृद्धि आयात की तुलना में लगभग दोगुनी है, समग्र स.घ.उ. सम्बन्धी निवल निर्यात के कम रहने की सम्भावना है। 2009-10 के त्वरित अनुमानों से यह सूचित हुआ है कि सकल घरेलू बचत दर 33.7 प्रतिशत और निवेश दर 36.5 प्रतिशत थी जो 2010-2011 में निवेश दर के सदृश स्तरों की तुलना में मौजूदा राजकोषीय सम्बन्धी सकल निर्धारित पूंजी निर्माण में विकास का स्तर प्रदर्शित करती है।

कृषि उत्पादन

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र हेतु 4 प्रतिशत की वार्षिक औसत विकास दर अनुमानित है। योजना के चार वर्षों (2007-11) में विकास की औसत वार्षिक दर 2.9 प्रतिशत थी। कृषि स.घ.उ. का विकास का निम्न स्तर मुख्यतः कृषि फसलों जैसे तिलहन, कपास, जूट तथा मेस्ता और गन्ने के उत्पादन में गिरावट की वजह से था, कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों में सकल पूंजी निर्माण कृषि स.घ.उ. के अनुपात के रूप में 2004-05 से 2006-07 के दौरान लगभग 14 प्रतिशत पर स्थिर रहा, तथापि, मौजूदा पंचवर्षीय योजना के दौरान आंकड़ों में महत्वपूर्ण सुधार दिखायी दिया। यह अनुपात 2007-08 में 16.03 प्रतिशत तक बढ़ गया और पुनः 2008-09 (अनन्तिम) में यह 19.67 प्रतिशत तथा 2009-10 (त्वरित अनुमान) में 20.30 प्रतिशत हो गया।

2008-09 में खाद्यान्न उत्पादन 234.47 मिलियन के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने के बाद घटकर 2009-10 में 218.11 मिलियन टन हो गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 9 फरवरी, 2011 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 232.07 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष यह 218.11 मिलियन टन था, यह 2008-09 में खाद्यान्न के रिकार्ड उत्पादन से कुछ ही कम था। देश को इस वर्ष गेहूं (81.47 मिलियन टन) दालें (16.51 मिलियन टन) तथा कपास (प्रति 170

किग्रा. की 33.93 मिलियन गांठें) का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त करने की सम्भावना है। बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में सूखे के कारण फसल को हुए नुकसान और देश के विभिन्न भागों में चक्रवात की मौसमी तथा भारी वर्षा, शीत लहर तथा पाला पड़ने के बावजूद उत्पादन का स्तर ऊंचा बना रहा।

कीमतें

वर्षानुवर्ष डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति, जो कि 2009-10 की आखिरी तिमाही में झलकी थी, चालू राजकोषीय वर्ष में भी लगातार बनी रही। विगत वित्त वर्ष के दौरान खराब मानसून के चलते दाल, खाद्यान्न तथा चीनी में अन्य मुद्रास्फीति द्वारा चालित खाद्यान्न कीमतें बढ़ी रहीं। इस साल अच्छे मानसून के बावजूद बढ़े हुए स्तरों पर हेडलाइन मुद्रास्फीति के कारण खाद्य स्फीति की दरें ऊंची बनी रहीं। वित्त वर्ष 2010-11 अप्रैल 2010 में 11.0 प्रतिशत की द्वि-अंकीय हेडलाइन मुद्रास्फीति के साथ शुरू हुआ था। इस क्रम में खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए प्रशासनिक तथा बृहद आर्थिक, दोनों ही स्तर पर कई कदम उठाए गए थे। अप्रैल से जुलाई 2010 तक द्वि-अंकीय रहने के बाद हेडलाइन मुद्रास्फीति घटकर एकल अंकीय हो गई। अगस्त 2010 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 8.8 प्रतिशत पर ठहर गई। नवम्बर 2010 में हेडलाइन स्फीति 8.1 प्रतिशत थी किंतु बाद में इन रुझानों ने पलटी ली और दिसम्बर 2010 में ये 8.4 प्रतिशत हो गए। खाद्य वस्तुओं में मंहगाई, जोकि नवम्बर 2010 में थोड़ी मंद हुई थी, फिर उछाल लेती हुई दिसम्बर 2010 में 13.6 प्रतिशत पर जा पहुंची। दिसम्बर 2010 में मुद्रास्फीति में आए इस उछाल की वजह सब्जियों, प्याज, टमाटर, फलों, दूध, अण्डों तथा मछली की आपूर्ति का अवरुद्ध हो जाना था। प्याज की फसल बरबाद होने के कारण दिसम्बर 2010 में प्याज की कीमतों में अचानक तेजी देखी गई। अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 की अवधि के दौरान प्राथमिक वस्तुओं में औसत मुद्रास्फीति 18 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि गतवर्ष की अवधि के दौरान यह औसतन 10 प्रतिशत रही थी। घरेलू अर्थव्यवस्था में बहाली ने मुद्रास्फीति पर मांग के पक्ष में एक दबाव बनाया। ग्लोबल रिकवरी के चलते यह स्फीतिकारी दबाव घरेलू मांग तथा उच्चतर ग्लोबल वस्तु मूल्यों, दोनों पर निरन्तर बना रहा। चूंकि थोक मूल्य सूचकांक के मुकाबले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य का महत्व अधिक होता है अतः मुद्रास्फीति, जोकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा ही मापी जाती है, नवम्बर 2008 से आगे थोक मूल्य सूचकांक में उच्च दर पर बनी रही। यह प्रवृत्ति चालू वित्तवर्ष में भी बनी रही। एक महीनों की अनवरत द्वि-अंकीय मुद्रास्फीति के बाद अगस्त 2010 में अखिल मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति घटकर एकल अंकीय स्तर पर आ पहुंची।

सीपीआई-आईडब्ल्यू में वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति दिसम्बर 2010 में 9.47 प्रतिशत रही जबकि गत वर्ष समान अवधि अर्थात् दिसम्बर 2009 में यह 14.97 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वर्षानुवर्ष आधार पर देखें तो कृषि

कामगारों के लिए सीपीआई-एएल तथा ग्रामीण कामगारों के लिए सीपीआई-आरएल में मुद्रास्फीति क्रमशः 7.99 तथा 8.01 प्रतिशत रही।

उद्योग तथा सेवाएं

2009-10 में अर्थव्यवस्था में तीव्र बहाली से विनिर्माण में सशक्त वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2008-09 में 3.2 प्रतिशत स्तर की तुलना में वर्ष 2009-10 में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (आईआईपी) बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया। वस्तुतः नवम्बर 2009 से मार्च 2010 के दौरान आईआईपी द्वि-अंकीय था। चालू वित्तवर्ष में वृद्धि में कुछ अस्थिरता देखी गई जिसमें नौ में से चार महीनों में वृद्धि दर द्वि-अंकीय बनी रही और शेष तीन महीनों में यह 5 प्रतिशत से भी कम रही। अंशतः यह आधारभूत प्रभाव के कारण था। सीएसओ द्वारा दिसम्बर 2010 के लिए आईआईपी पर जारी आंकड़ों के अनुसार, सूचकांक 1.6 प्रतिशत तक बढ़ा और अप्रैल-दिसम्बर 2010 के दौरान वृद्धि 8.6 प्रतिशत दर पर रही। आधार प्रभाव में यह गिरावट राह चलते हिचकोलों जैसी थी और आईआईपी वृद्धि की बेमौसमी माप से वृद्धि में हलचल दर्ज की गई। विनिर्माण क्षेत्र जिसका आईआईपी में 79.35 प्रतिशत भारांश है, मुख्य प्रेरक शक्ति रहा। विनिर्माण उत्पाद वृद्धि जो कि अप्रैल 2010 में 18 प्रतिशत के शिखर पर थी सहसा गिरी और दिसम्बर 2010 में 1.0 प्रतिशत पर आ गई, जिसके फलस्वरूप आईआईपी वृद्धि अप्रैल 2010 में 16.6 प्रतिशत से गिरकर दिसम्बर 2010 में 1.6 प्रतिशत हो गई। इस व्यापक विक्षोभ के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र के लिए अप्रैल-दिसम्बर 2010 की संचयी वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत रही। वास्तविक जीडीपी में 57.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र त्वरित वृद्धिमान प्रक्रिया की मुख्य चालक शक्ति बना रहा। भारत की सेवाएं स.घ.उ. वृद्धि समग्र स.घ.उ. वृद्धि को 1997-98 से पीछे छोड़ती हुई इससे निरन्तर अधिक बनी हुई है। 2010-11 के पूर्वार्ध के दौरान कुल निर्यातों में 35 प्रतिशत हिस्से और 27.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों में अधिक हिस्से के साथ सेवा क्षेत्र समग्र आर्थिक कार्यकलाप जिसमें रोजगार भी शामिल है, में महत्वपूर्ण है।

वैदेशिक क्षेत्र

बढ़े हुए चालू खाता घाटे का वित्तपोषण भारी अंतर्वाहों द्वारा होने के चलते वैदेशिक क्षेत्र का घटनाक्रम चालू वित्त वर्ष में विकास की रफ्तार का सहायक बना रहा। चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्ध के लिए उपलब्ध भुगतान संतुलन संबंधी आंकड़े चालू खाता घाटा अप्रैल-सितम्बर 2009 में 13.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर के मुकाबले 27.9 बिलियन अमरीकी डालर दर्शाते हैं। 39.1 बिलियन अमरीकी डालर के निवल अदृश्य अधिशेष के अपेक्षाकृत कम स्तर के साथ व्यापार घाटा 66.9 बिलियन अमरीकी डालर के अधिक स्तर होने से यह अंतर बढ़ गया। 2010-11 के पूर्वार्ध में 36.7

बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर निवल पूंजी प्रवाह 2009-10 के पूर्वार्ध में 23.0 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर की तुलना में अधिक थे। यह वृद्धि मुख्यतः पोर्टफोलियो निवेशमुख्यतः एफआईआई, अल्पावधिक व्यापार ऋण और विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के अंतर्वाहों के कारण हुई थी। तथापि, यह भारी वृद्धि भारत में आए निवल एफडीआई अंतर्वाहों में कमी के कारण प्रतिसंतुलित हुई थी। निवल पूंजी अंतर्वाहों में अच्छी खासी वृद्धि होने के बावजूद 2010-11 के पूर्वार्ध के दौरान मुद्रा भंडार में अनुवृद्धि अपेक्षाकृत कम हुई, जो मुख्यतः चालू खाते घाटे के 2009-10 के पूर्वार्ध में अपने स्तर से दुगुने से अधिक होने के कारण थी। विदेशी मुद्रा भंडार मार्चान्त 2009 में 252 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से बढ़कर मार्चान्त 2010 में 279.1 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया जो 27.1 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान मुद्रा भंडार अप्रैल-अंत 2010 में 279.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर नवम्बर-अंत 2010 में 292.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। यह मुद्रा भंडार मुख्यतः मूल्यन परिवर्तनों के कारण अपने मार्चान्त-2010 के स्तर में 18.2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्शाते हुए दिसम्बर 2010 के अंत में 297.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था।

चालू वित्त वर्ष के दौरान रुपये की मासिक औसत विनिमय दर सामान्यतः अपनी परिधि में बनी रही और अप्रैल तथा दिसम्बर 2010 के बीच प्रति बिलियन अमरीकी डालर 44-47 रुपये के दायरे में बढ़ती-घटती रही है। रुपये की विनिमय दर में अमरीकी डालर के मुकाबले 1.5 प्रतिशत की कमी आयी और यह अप्रैल 2010 में प्रति अमरीकी डालर 44.50 रुपये से गिरकर दिसम्बर 2010 में प्रति अमरीकी डालर 45.16 रुपये पर आ गई। इस अवधि के दौरान पाऊंड स्टर्लिंग (3.2 प्रतिशत) और जापानी येन (12.2 प्रतिशत) जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले रुपये के मूल्य में भी गिरावट आयी है।

मुद्रा, बैंकिंग और पूंजी बाजार

बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति तथा सुदृढ़ होते पुनरुत्थान के साथ स्फीतिकारी संभावनाओं पर उसके छा जाने की जोखिम को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 'संकट का प्रबंधन' से पुनरुत्थान बनाए रखना' की ओर स्पष्ट बदलाव की नीति अपनाई और कुछ क्षेत्रक-विशिष्ट सुविधाएं हटाकर तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक नकदी अनुपात का उसके संकट-पूर्व के स्तर पर लाकर अक्टूबर 2009 की दूसरी तिमाही समीक्षा में विस्तारकारी मौद्रिक नीति से से हटने के प्रथम चरण की घोषणा की थी। पुनरुत्थान के सुदृढ़ीकरण के स्पष्ट संकेत देखे जाने के चलते यह महसूस किया गया था कि मुख्य नीतिगत साधन तीव्र पुनरुत्थान करती अर्थव्यवस्था के अनुरूप होने के बजाय आर्थिक संकट की स्थिति के स्तरों से अधिक सुसंगत थे और यह आवश्यक था कि समायोजनकारी नीति के दृष्टिकोण से बाहर

निकलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 2010-11 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में छह बार वृद्धि की जिसमें एलएएफ के अंतर्गत मार्च 2010 से रेपो और रिवर्स दरों में संचयी रूप से 175 आधार बिन्दु और 200 आधार बिन्दु की बढ़ोतरी की तथा अब रेपो दर 6.5 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर 5.5 प्रतिशत है। आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) को बैंकों की निवल मांग तथा मीयादी देनदारियों (एनडीटीएल) को 6 प्रतिशत के स्तर पर रखा गया है। इस प्रकार, 2010-11 में मुद्रास्फीति के रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से लगातार अधिक बने रहने के साथ विकास में तेजी ने यह सुनिश्चित किया कि मौद्रिक नीति का केन्द्र मुद्रास्फीति और स्फीतिकारी संभावनाओं पर अंकुश लगाने बना रहा।

वर्षानुवर्ष खाद्य-भिन्न ऋण में वृद्धि दिसम्बर-अंत 2010 में बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई थी और इससे कई क्षेत्रों (कृषि में उछाल से लेकर 3जी स्पेक्ट्रम बिक्री तथा निजी क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाएं) का मोटे तौर पर वित्तपोषण हुआ, तथा समग्र ऋण और स.घ.उ. का अनुपात बढ़कर लगभग 47.8 प्रतिशत हो गया। घरेलू पूंजी बाजारों ने 2010 में अच्छा निष्पादन किया, प्राथमिक बाजार रिकार्ड स्तर पर वित्त पोषण कर रहे हैं जिसमें अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ (कोल इंडिया के लिए) शामिल है, जबकि द्वितीयक बाजारों ने नई ऊंचाई हासिल की। वित्त वर्ष के पहले सात महीने में विदेशी संस्थागत अंतर्वाहों में आए उछाल से बाजार को मदद मिली। पेंशन और बीमा क्षेत्र को लाभ हुआ, जब जीवन बीमा प्रीमियम में लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसकी पहुँच बढ़कर 2000 में (जब सुधार शुरू हुए) 2.3 प्रतिशत से दुगुनी होकर 2009 में स.घ.उ. का 5.4 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष बैंकिंग जमा में कम वृद्धि देखी गई क्योंकि वास्तविक ब्याज दरें विशेषतः अन्य तीव्र सुधार दर्शाने वाले आस्ति बाजारों (वास्तविक संपदा, स्वर्ण, और स्टाक बाजार) में मिलने वाले प्रतिलाभों की तुलना में कम थी।

केन्द्र सरकार की वित्त व्यवस्था

वर्ष 2009-10 में आर्थिक पुनरूत्थान के स्पष्ट प्रमाण जैसाकि स.घ.उ. के अग्रिम अनुमानों से प्रकट होता है, के चलते बजट 2010-11 में प्रोत्साहन उपायों से आंशिक निकासी के साथ राजकोषीय समेकन के रास्ते को फिर से चुना गया है। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटे का बजट 2010-11 तक 5.5 प्रतिशत अनुमान लगाया गया था तथा मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत विवरण में 2011-12 और 2012-13 में क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत की कटौती का उल्लेख किया गया

है। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में राजकोषीय परिणाम मोटे तौर पर बजट द्वारा तैयार किए गए समेकन के पथ पर बना रहा। टेलीकाम 3जी/बीडब्ल्यूए तथा अप्रत्यक्ष करों से अनुमान से अधिक राजस्व प्राप्त होने के फलस्वरूप चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान वर्षानुवर्ष राजस्व प्राप्तियों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को देखते हुए अधिक व्यय के लिए गुंजाइश थी। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में कुल व्यय में वर्षानुवर्ष वृद्धि 2010-11 के बजट अनुमानों में पूरे वर्ष के लिए कल्पित 8.5 प्रतिशत के मुकाबले 11.2 प्रतिशत रहने के चलते, राजकोषीय और राजस्व घाटा क्रमशः 171,249 करोड़ रुपये और 116,309 करोड़ रुपये आंका गया है, जो बजट अनुमानों का 44.9 प्रतिशत और 42.1 प्रतिशत बैठता है। सीएसओ के अग्रिम अनुमानों द्वारा पूरे वर्ष के लिए सांकेतिक स.घ.उ. को 78,77,947 करोड़ रुपये आंकने के चलते चालू वित्त वर्ष का लक्ष्य राजकोषीय घाटे और स.घ.उ. के अनुपात के संदर्भ में सं.अ. 2010-11 में 5.1 प्रतिशत और राजस्व घाटे के संदर्भ में 3.4 प्रतिशत रखा गया है।

संभावनाएं

2010-11 के लिए वास्तविक स.घ.उ. में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि के सीएसओ के अग्रिम अनुमान उपयुक्त हैं क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में संकेतकों के रूझान पर आधारित हैं। दिसम्बर 2010 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में गिरावट मुख्यतया आधार प्रभाव का प्रतिबिम्बन है और दिसम्बर 2010 के आईआईपी आंकड़ों के अनुसार मासिक दर मासिक मौसमीकृत आधार पर एक अन्तर्निहित वृद्धि की गति बनी हुई है। सेवा के महत्वपूर्ण उप सेक्टरों में तेजी के चलते और यह मानने पर कि मानसून सामान्य रहेगा, 2011-12 में वास्तविक स.घ.उ. के 9 प्रतिशत तक (+/-0.25 प्रतिशत) बढ़ने की संभावना है। वृद्धि के अनुमानों में कमी लाने के लिए ये जोखिम हो सकते हैं- सामान्य से कम मानसून वस्तुओं, विशेषकर कच्चे तेल के मूल्य में तीव्र वृद्धि और उभरती हुई वैश्विक विशेषकर राजकोषीय प्रोत्साहनों के अभाव में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक स्थिति, ग्यारहवीं योजना के लिए अनुमानित 4.1 प्रतिशत के वृद्धिशील पूंजी उत्पादन के स्तरों के चलते उच्चतर पूंजी निर्माण तथा कुल उपादान उत्पादकता के संदर्भ में प्राप्त लाभों के कारण उच्चतर वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगले पांच से दस वर्ष में, पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण होगा और एक बार अर्थव्यवस्था के इसकी क्षमता के अनुरूप चल पड़ने पर, देश में कौशल विकास और अभिनव क्रियाकलाप स.घ.उ. वृद्धि के प्रभावी उत्प्रेरकों के रूप में बचतों और निवेश दरों का स्थान ले लेंगे।

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण
(आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-दिसम्बर		प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
वास्तविक क्षेत्र					
1.	उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)*				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	6133	7257	16.1	18.3
	(ख) 2004-2005 के मूल्यों पर	4494	4879	8.0	8.6
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (1993-94=100)	304.7	331.0	8.6	8.6
3.	शोक मूल्य सूचकांक (आधार 2000-05=100) @	128.8	140.9	1.7	9.4
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:औद्योगिक कामगार (2001=100)	160.1	177.7	11.3	11.0
5.	मुद्राआपूर्ति (एम3) (हजार करोड़ रुपए)\$	5285	6202	17.7	17.4
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात**				
	(क) करोड़ रुपए	991605	1126513	-12.0	13.6
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	207315	246724	-18.3	19.0
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात **				
	(क) करोड़ रुपए	608882	751633	-6.7	23.4
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	127182	164707	-13.8	29.5
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर) **	-80133	-82017	-24.6	2.4
9.	विदेशी मुद्रा भंडार				
	(क) करोड़ रुपए में	1323235	1332353	6.7	0.7
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर में	283470	297334	10.7	4.9
10.	चालू लेखा शेष (मिलियन अमरीकी डालर में) (अप्रैल-सितंबर)	-13339	-27881
सरकारी वित्त साधन #					
1.	राजस्व प्राप्तियां	389271	584268	3.5	50.1
2.	कर राजस्व (निवल)	307591	391148	-0.8	27.2
3.	कर-भिन्न राजस्व	81680	193120	23.7	136.4
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	318269	202584	43.8	-36.3
5.	ऋणों की वसूली	3983	8591	33.9	115.7
6.	अन्य प्राप्तियां	22744	9914.0	428.2	
7.	उधार और अन्य देनदारियां	309980	171249	42.0	-44.8
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	707540	786852	18.5	11.2
9.	आयोजना-भिन्न व्यय (10+12)	497381	536898	16.6	7.9
	जिसमें:				
10.	राजस्व खाता	460970	487692	14.2	5.8
	जिसमें:				
11.	ब्याज भुगतान	130005	146304	5.1	12.5
12.	पूंजी खाता	36411	49206	60.7	35.1
13.	आयोजना व्यय (14+15)	210159	249954	23.0	18.9
	जिसमें:				
14.	राजस्व खाता	179555	212885	23.0	18.6
15.	पूंजी खाता	30604	37069	23.5	21.1
16.	कुल व्यय (9+13)	707540	786852	18.5	11.2
17.	राजस्व व्यय (10+14)	640525	700577	16.5	9.4
18.	पूंजी व्यय (12+15)	67015	86275	41.2	28.7
19.	राजस्व घाटा (17-1)	251254	116309	44.5	-53.7
20.	राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	309980	171249	42.0	-44.8
21.	प्रारम्भिक घाटा (20-11)	179975	24945	90.4	-86.1

त्व.अ. त्वरित अनुमान; अ.अ. अग्रिम अनुमान

* पूर्ण वर्ष से संबंधित

@ अप्रैल से दिसम्बर की औसत

\$ एम₃ संबंधी आंकड़े वर्ष 2009-10 के लिए 1 जनवरी, 2010 की स्थिति के अनुसार और 2010-11 के लिए 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं।

** सीमाशुल्क आधार पर; संशोधित आधार की तुलना में अनन्तिम आधार पर चालू वर्ष हेतु तुलनात्मक अध्ययन।

लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े